बारिश से टूटी सड़कों को सुधारने के लिए 1445 करोड़ रुपए का बजट आवंटित

इनमें से 645 करोड़ रु. पेचवर्क रिपेयरिंग तथा 800 करोड़ रु. स्थायी मरम्मत पर खर्च होंगे

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । मुख्य सचिव सुधांश पंत ने मंगलवार को सचिवालय में सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा एन.एच.ए.आई. की परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वर्षा से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत को राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता मानते हुए गुणवत्तापूर्ण कार्य करें। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने बारिश से टूटी सड़कों को सुधारने के लिए 1445 करोड़ रु. का बजट आवंटित किया है।

इनमें से 645 करोड़ रु. पेचवर्क रिपेयरिंग तथा 800 करोड़ रु. स्थायी मरम्मत पर खर्च होंगे। मुख्य सचिव ने पेच रिपेयर कार्य 15 नवम्बर तक उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए दूसरे विभागों के इंजीनियर्स से इन कामों की जांच करवाई जाएगी।

मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भावना के अनुरूप सभी अधिकारी ईमानदारी से काम करते हुए फील्ड में सक्रिय रहकर स्वीकृत कार्यों को समय पर पूर्ण करवाएं। सिर्फ अपवाद की स्थिति में ही निविदा की तिथि को आगे बढ़ाएं।

अन्यथा निविदा खोलने से वर्क ऑर्डर जारी करने तक निर्धारित टाइमलाइन का सख्ती से पालना किया जाए तथा उसका निरीक्षण ऑनलाईन माध्यम से करें।

मुख्य सचिव सुधांश पंत ने मंगलवार को सचिवालय में सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा एन.एच.ए.आई. की परियोजनाओं की समीक्षा की।

स्पेशल टास्क फोर्स गठन के निर्देश

बैठक में मुख्य सचिव ने एनएचएआई-एनएच के कार्यों में अन्तर्विभागीय मुद्दों के त्वरित निस्तारण के लिए स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने के निर्देश दिए। टास्क फोर्स में वन, राजस्व, विद्युत व अन्य सम्बंधित विभागों के अधिकारियों को शामिल किया जाएगा।

उन्होंने एनएचएआई की 7919 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि प्रदेश में चल रही इन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को समय पर पूर्ण करने के लिए पूर्ण सहयोग एवं सामंजस्य से काम करें।

लम्बित कामों को मार्च तक पूरा करें

मुख्य सचिव ने पीडब्ल्यूडी के 50 करोड़ रुपये की लागत से अधिक के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि जो 35 लम्बित कार्य 90 प्रतिशत तक पूर्ण हो चुके हैं, उन्हें 31 दिसम्बर तक एवं शेष 8 कार्यों को मार्च, 2026 तक पूर्ण करें।

गौरतलब है कि पीडब्ल्यूडी के 50 करोड़ रुपये की लागत से अधिक के 33 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, 31 निर्धारित समयावधि में चल रहें हैं एवं 43 कार्यों की निर्धारित समयावधि निकल चुकी है।

पी.एम.आई.एस. की सराहना की

मुख्य सचिव ने विभाग द्वारा प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग के लिए काम लिए जा रहें प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग इंफर्मेशन सिस्टम की सराहना करते हुए कहा कि इसे और सुदृढ़ किया जाए।

उन्होंने निर्देश दिए कि इसमें हर प्रोजेक्ट की प्रत्येक स्थिति की 3-4 उच्च गुणवत्ता की फोटो डाली जाए। इसके साथ ही, उन्होंने डीएलपी सड़कों के निरीक्षण के लिए विभाग द्वारा विकसित किए गए सुगम पथ एप की लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।

- **मुख्य सचिव सुधांश पंत ने अफसरों को प्रदेश की क्षतिग्रस्त सड़कें प्राथमिकता और गुणवत्ता के साथ सुधारने के निर्देश दिए**

हर माह होगी बड़े प्रोजेक्टस की समीक्षा

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए है कि सरकार की मंशा के अनुरूप बजट घोषणाओं एवं मुख्यमंत्री घोषणाओं को समय पर पूर्ण कर आमजन को उनका शीघ्र लाभ सुनिश्चित करने के लिए विभाग के प्रोजेक्टस की हर माह समीक्षा की जाएगी।

गत 2 वर्षो में 36140 कि.मी.लम्बी सड़कों का निर्माण हुआ

अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता ने बैठक में बताया कि बजट घोषणा 2024-25 व 2025-26 के तहत लगभग 15 हजार करोड़ रुपये की लागत के 12 हजार से अधिक कार्य स्वीकृत किये गये हैं, जिनमें से अधिकांश कार्य आरंभ करवाये जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि विगत 2 वर्षो में 24,976 करोड़ रुपये व्यय कर 36140 कि.मी. लम्बाई की सड़कों का विकास प्रदेश में करवाया जा चुका है। इस दौरान सार्वजनिक निर्माण विभाग के उच्च अधिकारी उपस्थित रहे।

सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक जिलों में होगी पदयात्राएं

जयपुर में 31 अक्टूबर को प्रातः 6 बजे गांधी सर्किल से शुरू होगी पदयात्रा

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । केन्द्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने गत 6 अक्टूबर को सरदार150 कम्यूनिटी मार्च अभियान शुरू किया है। 2 माह तक चलने वाले इस राष्ट्रीय अभियान का समापन आगामी 6 दिसम्बर को होगा। इस अभियान को पूर्ण जन भागीदारी से संचालित कर देशवासियों विशेषकर युवाओं को सरदार पटेल की विरासत के बारे में जागरूक कर विरासत के प्रति व्यक्तिगत और सामूहिक कृतज्ञता अर्पित करने, उनमें राष्ट्रीय एकता और देश सेवा की भावना को अधिक विकसित करना है।

31 अक्टूबर से 25 नवम्बर तक जिला स्तरीय पदयात्राएं आयोजित होंगी। 26 नवम्बर को सरदार पटेल की जन्म स्थली करमसाड़ से 150 किमी लम्बी पदयात्रा शुरू होगी। इस पदयात्रा के 6 दिसम्बर को एकता नगर (स्टेच्यू ऑफ यूनिटी) पहुंचने के साथ ही अभियान का समापन होगा। आगामी 31 अक्टूबर को प्रातः 6 बजे जयपुर के गांधी सर्किल से एकता मार्च का भव्य शुभारंभ किया जाएगा। एकता मार्च का मार्ग जयपुर के गांधी सर्किल से बिड़ला मंदिर रामबाग, अंबेडकर सर्किल होते हुए अमर जवान ज्योति तक रहेगा।

- **इसके बाद 26 नवम्बर को सरदार पटेल की जन्म स्थली करमसाड़ से 150 किमी लम्बी पदयात्रा शुरू होगी, जो 6 दिसम्बर को एकता नगर (स्टेच्यू ऑफ यूनिटी) पहुंचने के साथ संपन्न होगी**

इस अभियान में युवा मामले, शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन, सूचना एवं जनसम्पर्क और गृह विभाग, माई भारत और एनएसएस के कार्मिक सक्रिय भूमिका निभाएंगे।

यह अभियान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने में महत्वपूर्ण कड़ी है। नागरिकों को पदयात्रा, प्रतियोगिता आदि पहल के माध्यम से इस अभियान से जोड़ा जा रहा है। यूनिटी मार्च सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के सम्मान में एक राष्ट्रव्यापी पहल है। यह श्एक भारतकृ श्रेष्ठ भारत के घटक के रूप में देश को एकजुट करने में सरदार पटेल की अद्वितीय भूमिका का प्रतीक है, यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित और आत्मनिर्भर भारत के मिशन की कड़ी है। इस अभियान में युवाओं की बेहतर भागीदारी के लिए सरदार150 यंग लीडर्स क्विज, सरदार150 रील कम्पीटिशन और सरदार150 निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है।

पदयात्रा के साथ-साथ जिलों में विकासात्मक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जल निकायों में स्वच्छता अभियान, सरदार उपवन पहल के तहत पौधारोपण, महिला कल्याण शिविर, योग और स्वास्थ्य शिविर और वोकल फॉर लोकल अभियान शामिल हैं।

इन गतिविधियों का उद्देश्य नागरिकों को जुटाना, स्थानीय नवाचार का जश्न मनाना और युवा ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण में लगाना है।

'खतरनाक यात्री बसों के संचालन पर प्रभावी कार्रवाई करें'

जयपुर । राज्य मानवाधिकार आयोग ने मनोहरपुर में यूपी के पीलीभीत से आ रही बस के हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से आग लगने और उसमें बैठे कई यात्रियों के मरने के हादसे में स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लिया है। वहीं परिवहन आयुक्त से कहा है कि उनसे अपेक्षा है कि वे प्रदेश में चल रही यात्री बसों की सुरक्षा के मापदंडों को सुनिश्चित करें। इसके अलावा खतरनाक यात्री बसों के संचालन पर प्रभावी कार्रवाई करें। वे यह भी देखें की बसों में यात्रियों की सुरक्षा के पूरे इंतजाम हों और मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों की पालना की जाए। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस जीआर मूलचंदानी ने यह आदेश मनोहरपुर बस हादसे पर प्रसंज्ञान लेते हुए दिए।

राज्यपाल बागड़े से उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी की भेंट

जयपुर। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मंगलवार को राजभवन में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ने राज्यपाल को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की। शिष्टाचार भेंट के दौरान दोनों के बीच राज्य के जनकल्याणकारी विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। राज्यपाल ने उपमुख्यमंत्री को अपने प्रेरणादायी मार्गदर्शन से अवगत कराया तथा राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य करने का आव्हान किया।

भजनलाल सरकार ने करीब 5 लाख किसानों से अब तक खरीदी 8191 करोड़ रुपये की उपज

राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से कृषक लाभांवित

जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। किसानों को उनकी उपज का उचित दाम मिले, इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद योजना का राज्य में प्रभावी क्रियान्वयन कर किसानों से बड़े स्तर पर कृषि जिंसों की खरीद की जा रही है। समर्थन मूल्य पर वृहद् स्तर पर हो रही खरीद से किसानों को बाजार की अनिश्चितताओं से मुक्ति मिल रही है और उनकी सुनिश्चित आय हो रही है।

सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने बताया कि वर्तमान राज्य सरकार के 2 वर्ष से भी कम अवधि के अब तक के कार्यकाल में पूर्ववर्ती सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल की तुलना में विभिन्न जिंसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आनुपातिक दृष्टि से अधिक खरीद कर किसानों को प्रत्यक्ष रुप से लाभान्वित किया गया है।

- **प्रदेश में मूंग, मूंगफली और सोयाबीन की हुई रिकॉर्ड खरीद**

उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक लगभग 5 लाख किसानों से 8 हजार 191 करोड़ रुपये की उपज खरीदी जा चुकी है। वहीं, खरीफ-2025 सीजन में भी एमएसपी पर कृषि जिंस बेचान के लिए बड़ी संख्या में किसान अपना पंजीयन करवा रहे है। दक ने बताया कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में 5 वर्ष में 2827 करोड़ रुपये राशि का 3.90 लाख मीट्रिक टन मूंग किसानों से खरीदा गया था, जिसकी तुलना में वर्तमान सरकार के 2 वर्ष से भी कम अवधि के कार्यकाल में 1720 करोड़ रुपये का भुगतान कर किसानों से लगभग 2 लाख मीट्रिक टन मूंग खरीदा जा चुका है।

उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में मूंगफली रिकॉर्ड खरीद की गई है। पूर्ववर्ती सरकार के पूरे कार्यकाल में 1 लाख 74 हजार 656 किसानों से 2058 करोड़ रुपये राशि की 4.79 लाख मीट्रिक टन मूंगफली खरीदी गई थी। जबकि, वर्तमान सरकार के अब तक के कार्यकाल में ही 1 लाख 42 हजार 58 किसानों से 3 हजार 269 करोड़ रुपये राशि की 4 लाख 84 हजार 687 मीट्रिक टन मूंगफली खरीदी जा चुकी है।

मादक पदार्थ तस्करों को 10 साल की सजा

जयपुर । एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत, महानगर प्रथम ने मादक पदार्थ कोकीन की तस्करी करने वाले अभियुक्त तैय्यब रहमान और रविन्द्र टकसाली को दस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्तों पर 2.45 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी प्रदीप कुमार मोदी ने अपने आदेश में कहा कि मौजूदा समय में मादक पदार्थ के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। मादक पदार्थ आसानी से उपलब्ध होने के चलते युवा वर्ग इसकी चपेट में आ रहा है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तों के प्रति किसी तरह की नरमी नहीं बरत सकते।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक शंकर लाल ने बताया कि विभाग की क्षेत्रीय इकाई जोधपुर के आसूचना अधिकारी को 10 मार्च 2023 को गोपनीय सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति तैय्यब रहमान लोक परिवहन की बस में बैठकर अपने बैग में कोकीन छिपाकर दिल्ली से जयपुर लाएगा। यह बस 13 मार्च 2023 को नारायण सिंह सर्किल पर शाम 6 से 6.30 बजे आएगी।

अगले माह होंगे नए वेटरनरी कॉलेज के लिए आवेदन

जयपुर । प्रदेश में नए वेटनरी डिप्लोमा व डिग्री कॉलेज खोलने के लिए पशुपालन विभाग फिर से आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ करेगा।

इसके लिए नवंबर-2025 में सात दिन के लिए पोर्टल खोला जाएगा, जिसमें ऑनलाइन आवेदन भरे जा सकेंगे। शासन सचिवालय में पशुपालन विभाग की समीक्षा बैठक में गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने यह निर्देश दिए।

इस समीक्षा बैठक में राज्य की दोनों वेटनरी यूनिवर्सिटी से एफिलेटिड कॉलेजों में नए शिक्षा सत्र में सेटूलाइज्ड काउंसलिंग सिस्टम के तहत प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित करने, यूनिवर्सिटी के रेफरल हॉस्पीटल में निःशुल्क दवाएं उपलब्ध करवाने सहित विभिन्न मुददों पर चर्चा हुई।

आयुक्त डॉ. निधि पटेल ने निरीक्षण किया तो हैरिटेज निगम में नदारद मिले अफसर

जयपुर । नगर निगम जयपुर हैरिटेज की आयुक्त डॉ. निधि पटेल ने मंगलवार को निगम मुख्यालय पर औचक निरीक्षण किया, इस दौरान मुख्यालय में ड्यूटी पर लेट आने वाले पाए अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया। आयुक्त डॉ. निधि पटेल ने बताया कि निगम ऑफिस में प्रतिदिन जांच की जाएगी। जोन कार्यालय में भी औचक निरीक्षण कर अधिकारियों के कामकाज की मॉनिटरिंग की जाएगी।

इसके बाद आयुक्त डॉ. निधि पटेल ने सभी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान निगम आयुक्त डॉ निधि पटेल ने अनुशासन, राजस्व सुधार और सफाई व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। आयुक्त डॉ. पटेल ने कहा कि निगम की कार्यप्रणाली में समयबद्धता और जिम्मेदारी सबसे आवश्यक है। उन्होंने चेतावनी दी कि ड्यूटी के समय अनुपस्थित रहने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और वेतन नहीं दिया जाएगा।

आयुक्त ने कहा कि निगम की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए राजस्व वसूली में गति लाना जरूरी है। इसके लिए अब हर सप्ताह टैक्स कलेक्शन की समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को लक्ष्य निर्धारित कर कार्य करने के निर्देश दिए और कहा कि वार्ड स्तर पर लंबित बकाया वसूली को प्राथमिकता दी जाए। आयुक्त डॉ. पटेल ने निर्देश दिए कि पर्यटन स्थलों और ऐतिहासिक क्षेत्रों की सफाई व्यवस्था पर विशेष फोकस रखा जाए, ताकि जयपुर की स्वच्छता और सुंदरता देश-विदेश के पर्यटकों के समक्ष बनी रहे।

खान विभाग ने 26 अक्टूबर तक 486 करोड़ का राजस्व कमाया : टी. रविकांत

''यह राजस्व गत वर्ष की इस अवधि की तुलना में 115 करोड़ रु. ज्यादा है''

खान विभाग के प्रमुख सचिव टी. रविकान्त ने मंगलवार को सचिवालय में हाईब्रिड मोड पर विभागीय अधिकारियों की बैठक ली।

जयपुर (कासं)। खान विभाग के प्रमुख सचिव टी. रविकान्त ने कहा है कि बड़े राजस्व लक्ष्य को प्राप्त करना बड़ी चुनौती है, पर इसे समन्वित प्रयासों से अर्जित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 26 अक्टूबर तक विभाग द्वारा गत वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 115 करोड़ रुपए अधिक राजस्व संग्रहित करते हुए 4866 करोड़ 17 लाख रुपए का राजस्व संग्रहित किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष के आगामी माहों में हमें राजस्व छीजत रोकने, अधिक से अधिक राजस्व वसूल करने और माइनिंग सेक्टर में राजस्व वसूली के लक्ष्य को अर्जित करने संकल्प के साथ आगे बढ़ ना होगा। गत वित्तीय वर्ष में इस अवधि तक 4751 करोड़ 57 लाख रुपए का राजस्व जमा हुआ था। प्रमुख सचिव माइंस टी. रविकान्त मंगलवार को सचिवालय में हाईब्रिड मोड पर विभागीय अधिकारियों की बैठक ले रहे थे।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा माइनिंग सेक्टर में राजस्थान को अग्रणी प्रदेश बनाने और नित नए आयाम स्थापित करने पर जोर देते रहे है। इसलिए निदेशालय सहित फील्ड अधिकारियों को मोनेटरिंग और एनालिसिस सिस्टम को और अधिक मजबूत करने के निर्देश दिए। किन्ही कारणों से अभी तक जहां आरसीसी-ईआरसीसी ठेके नहीं हो पाये हैं वहां कम राजस्व वसूली पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने विभागीय मशीनरी को चाकचोबंद करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि अधिकारियों को रुटिन के काम के साथ ही सस्टेनेबल माइनिंग, माइनिंग प्लान के अनुसार माइनिंग, सुरक्षा मानकों की पालना सहित माइनिंग लीजों में हो रहे खनिज उत्पादन का विश्लेषण भी करना चाहिए कि पहले से कम या ज्यादा उत्पादन हो रहा है तो उसके क्या कारण है? उत्पादन के अनुसार रायल्टी आदि जमा हो रही है या नहीं और इसके साथ ही अवैध खनन गतिविधियों पर सख्ती से कार्रवाई करने में कोताही नहीं बरती जाए।

रविकान्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि अतिरिक्त निदेशकों और अधीक्षण अभियंताओं का दायित्व है कि वे अपने स्तर पर नियमित समीक्षा करे और आवश्यकतानुसार अधीनस्थ अधिकारियों को मार्गदर्शन, सहयोग और समन्वय बनाएं ताकि बेहतर परिणाम प्राप्त हो सके। उन्होंने माइनर मिनरल ब्लॉकों के डेलिनियेशन से लेकर ऑक्षन के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।

निदेशक माइंस महावीर प्रसाद मीणा ने बताया कि विभाग द्वारा राजस्व लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीति तैयार कर क्रियान्विति आरंभ कर दी है।संयुक्त सचिव माइंस अरविन्द सारस्वत ने ई-फाइलिंग निष्पादन में समय सीमा कम करने, विधानसभा प्रश्नों के उत्तर भिजवाने, विभाग से संबंधित समाचारों पर आवश्यकतानुसार टिप्पणी भिजवाने, मुख्यमंत्री कार्यालय सहित अन्य पत्रों के तत्काल उत्तर भिजवाने की आवश्यकता प्रतिपादित की। हाईब्रिड बैठक में ओएसडी श्रीकृष्ण शर्मा, एसजी एरियल सर्वे सुनील वर्मा, एसएमई विजिलेंस प्रताप मीणा, एसजी संजय सक्सैना उपस्थित रहे।

मतदाता सूची का पुनरीक्षण देशहित में कदम : मदन राठौड

जयपुर, (कासं)। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण और शुद्धिकरण की प्रक्रिया को सकारात्मक और देश हितकारी पहल बताया। राठौड़ ने कहा कि एसआरआर कार्य न केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करेगा, बल्कि मताधिकार के दुरुपयोग को भी रोकने में सहायक सिद्ध होगा। राठौड़ ने कहा कि हर बार की तरह इस बार भी निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जा रहा है, जिसमें मृत व्यक्तियों के नाम हटाने और नए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने की प्रक्रिया शामिल है। राजस्थान में भी इस प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है, ताकि केवल वैध और योग्य नागरिक ही मताधिकार का उपयोग कर सकें। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि दुर्भाग्यवश, बीते वर्षों में कुछ राजनीतिक दलों ने अपने स्वार्थवश ऐसे लोगों के नाम मतदाता सूची में जुड़वा दिए हैं, जो इस देश के नागरिक नहीं हैं। कुछ क्षेत्रों में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम भी मतदाता सूची में शामिल होने की शिकायतें मिली हैं। ऐसे लोग भारत को एक धर्मशाला की तरह समझकर यहां केवल लाभ उठाने आते हैं, परंतु राष्ट्रिहत या जनसेवा से उनका कोई सरोकार नहीं होता। ऐसे अवैध रूप से जुड़े नामों को मतदाता सूची से हटाना पूरी तरह उचित और आवश्यक कदम है। उन्होंने विपक्षी दलों की आलोचना करते हुए कहा कि जो दल इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं।

खाटूश्यामजी कॉरिडोर के विकास कार्यों पर उपमुख्यमंत्री ने की चर्चा

यातायात व्यवस्था, अतिक्रमण और पार्किंग की समस्याओं के समाधान के लिए विशेष कमेटी भी बनाई, जो कि जल्द ही ठोस सुझाव प्रस्तुत करेगी

जयपुर (कासं)। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में मंगलवार को पर्यटन भवन में स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत श्री खाटूश्यामजी कॉरिडोर (सीकर) के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव, अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आरएसआरडीसी, पीडीकोर, मंदिर कमेटी पदाधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल हुए।

बैठक के दौरान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि श्री खाटू श्याम जी राजस्थान की सबसे प्रमुख धार्मिक नगरी है, जहां हर वर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। उन्होंने कहा कि यह राज्य के लिए गर्व का विषय है, लेकिन इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी है कि श्रद्धालुओं को बेहतर और सुगम अनुभव मिल सके।

- **उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि ''जनप्रतिनिधियों व स्थानीय सुझावों से ही इस कॉरिडोर का विकास और अधिक प्रभावी होगा''**

दिया कुमारी ने बताया कि भारत सरकार के स्वदेश दर्शन 2.0 कार्यक्रम के अंतर्गत खाटूश्यामजी में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक माहौल में की गई। यातायात व्यवस्था, अतिक्रमण और पार्किंग की समस्याओं के समाधान के लिए एक विशेष कमेटी गठित की गई है, जो जल्द ही ठोस सुझाव प्रस्तुत करेगी।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में मंगलवार को पर्यटन भवन में स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत श्री खाटूश्यामजी कॉरिडोर के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक हुई।

उप मुख्यमंत्री ने कहा, दर्शनार्थियों एवं स्थानीय निवासियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए और सभी स्टेक होल्डर्स व जनप्रतिनिधियों के सुझावों को शामिल कर विकास कार्य करना ही अधिक प्रभावी होगा। उन्होंने यह भी बताया कि कमेटी द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर राजस्थान सरकार के आगामी बजट में भी इस परियोजना के लिए राशि का प्रावधान किया जा सकता है।

बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर भावना शर्मा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजस्थान मेला प्राधिकरण अशोक कुमार सांखला, अतिरिक्त निदेशक पर्यटन विभाग आनन्द कुमार त्रिपाठी, एसडीएम मोनिका सारस्वत, एएसपी दीपक गर्ग, श्री श्याम मंदिर कमेटी अध्यक्ष पृथ्वी सिंह चौहान, खाटूधाम व्यापार मण्डल अध्यक्ष सोनू जोशी, पूर्व चेयरमैन पवन पुजारी, तथा पीडीकोर और आरएसआरडीसी के अधिकारी उपस्थित रहे।